जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 47 संख्याः 285 प्रभात कोटा, गुरुवार 28 जुलाई, 2022 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

*स्पॉटेड हायना (लकड़बग्घे की एक प्रजाति) ने तंज़ानिया के विख्यात सैरेन्गेटी नैशनल पार्क में जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन कर लिया है। यह देखकर शोधकर्ता हैरान हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि, बारिश का पैटर्न बदलने से इन्हें बच्चों पर ध्यान देने की बजाय शिकार ढूंढने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि, गत तीन दशकों के आंकड़े देखें तो सैरेन्गेटी में बारिश ज्यादा होने लगी है और ब्लू विल्डबीस्ट जैसे शाकाहारी जानवरों के झुंडों के माइग्रेशन का समय भी बदल रहा है। इसका अर्थ है कि, हायना को हमेशा जिस स्थान पर तथा जिस समय भोजन मिलता आया है, वहां शायद ना मिले। जर्नल इकोस्फिअर में प्रकाशित शोध में मुख्य लेखक मॉर्गैन ज़ीकैल ने कहा, गत दशक में माइग्रेशन करने वाले झुण्ड हायना की टैरिटरी में देर से आ रहे हैं। विल्डबीस्ट व अन्य प्रवासी जंतु, जैसे ज़ीब्रा और थॉमसन्स गज़ैल स्पॉटेड हायना का प्रमुख भोजन हैं। जब इनके झुण्ड नहीं होते हैं तब हायना अन्य नॉन माइग्रेटरी जीवों, जैसे बफलो, टोपी एवं इम्पाला जैसे एंटीलोप खाते हैं। जून के आसपास विल्डबीस्ट भोजन व पानी के लिए पार्क के उत्तर पश्चिम भाग में जाते हैं व अक्टूबर में वर्षा आने पर लौटते हैं। इनके साथ लाखों ज़ीब्रा व गज़ैल भी माइग्रेशन करते हैं। ज़ीकैल व उनके सहयोगियों ने सैरेन्गेटी नैशनल पार्क में 1.48 मिलियन हैक्टेयर में फैले हायना के तीन अलग-अलग समूहों की गुफाओं के 30 साल के डेटा का अध्ययन किया। हायना वर्ष भर प्रजनन करते हैं और शोधकर्ता सोच रहे थे कि नवजात बच्चों को दूध पिलाने वाली मादाओं का गुफा के आसपास रहना कम हो गया होगा, क्योंकि उन्हें अपना दूध बढ़ाने के लिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर ज्यादा समय देना पड़ता होगा। लेकिन आंकड़ों से सामने आया कि बारिश ज्यादा होने के साथ ही जब हायना की टैरिटरी में माइग्रेटरी जानवरों की संख्या कम हो गई, तब भी बच्चों को दूध पिलाने वाली मादाएं अपनी गुफा पर बच्चों के साथ उतना ही समय बिता रही थीं, जितना पहले बिताती थीं। गुफाओं के पास मादा हायना की उपस्थिति के समय में परिवर्तन नहीं होना इस आइडिया से मेल खाता है कि, जब स्पॉटेड हायना के वातावरण में परिवर्तन होता है तब भी उनकी प्रतिक्रिया आमतौर पर लचीली होती है, अर्थात् वो आसानी से बदलाव के साथ अनुकूलन कर लेते हैं और मजबूत रहते हैं।*

# महाराष्ट्र में 30 जून से नयी सरकार ने कार्यभार संभाला

## पर अभी दो ही कैबिनेट मंत्री, शिंदे व फड़नविस हैं मंत्रिमण्डल में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिन्दे की गठबंधन सरकार, जिसमें भाजपा एवं शिवसेना का विद्रोही गुट शामिल हैं, के मंत्रिमंडल में पिछले 27 दिन से, अर्थात् 30 जून से केवल दो ही व्यक्ति हैं। इसके विस्तार की कोई सन्निकट सम्भावना दिखाई न देने के कारण, राज्य के 13 करोड़ लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जून के महीने में, एकनाथ शिन्दे तथा फड़नवीस ने भाजपा हाईकमान के निर्देशों और आशीर्वाद के साथ, एक साथ मिलकर सेना के विधायकों को उद्धव ठाकरे से अगल करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी।

जहाँ नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुये, माँग की है कि राज्य सरकार को तत्काल विधानसभा सत्र बुलाना चाहिये तथा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिये, वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर आँखें बंद किये हुये है। दरअसल, भाजपा नेतृत्व को डर है कि, मंत्रिमंडल विस्तार से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भाजपा विधायक भी मंत्री पद की माँग कर रहे हैं इसलिए शिव सेना के कुछ विद्रोही विधायक असंतुष्ट हो सकते हैं।

शिन्दे तथा फड़नवीस की जोड़ी के लिए ठाकरे सरकार गिराना कदाचित् आसान था। उन्होंने जाँच एजेंसियों की धमकियों तथा मंत्री पद की पेशकश के जरिये ठाकरे सरकार को गिरा दिया था, क्योंकि इस दोनों कारणों से, शिवसेना विधायक भाजपा की गोद में बैठने के लिये भागे थे। लेकिन बाद की खुशी बड़ी अल्पजीवी सिद्ध हुई।

मुख्य समस्या लूट के माल के बंटवारे की है। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की जल्दबाजी में, शिन्दे और फड़नवीस ने सेना को छोड़ने वाले विधायकों से बड़े-बड़े वादे कर दिये और अब उन वादों को पूरा करने में मुश्किल आ रही है तथा "बिग ब्रदर" के रुप में भाजपा अधीरता दर्शाते हुये अपेक्षाकृत बड़े हिस्से के लिये दावा कर रही है।

फड़नवीस, जो पिछली भाजपा-शिवसेना सरकार में मुख्यमंत्री थे, पर अपने अहम् को भूल जाने के लिये दबाव पड़ा तथा परिणामस्वरुप, उन्हें शिन्दे (जिन्होंने कभी उनके अधीन काम किया था) के नीचे अनिच्छापूर्वक उपमुख्यमंत्री बनने के लिये सहमत होना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा, विधायकों की दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, अतः स्वाभाविक ही भाजपा विधायकों की शिकायत है कि, हमें क्या मिला। उनका कहना है, फड़नविस को कम से कम उपमुख्यमंत्री का ओहदा व सुविधाएं तो मिलीं।
- शिव सेना विधायकों से भी बहुत लम्बे-चौड़े वादे किये गये थे, ठाकरे सरकार को गिराते समय, वे विधायक भी वादे पूरे होने की आस लगाये बैठे हैं।
- फड़नविस ने भी मन मार कर, उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था, अतः अपनी कुर्बानी के एवज में, कम से कम भारी विभाग तो चाहते हैं।
- दूसरी ओर शिंदे बड़े विभाग, पी.डब्ल्यु.डी., होम व फाइनैंस अपने पास रखना चाहते हैं।
- इन सब दुविधाओं के बीच शिंदे व फड़नविस, कम से कम पांच बार दिल्ली की यात्रा कर चुके हैं और नड्डा व शाह से मिले हैं, पर, अभी दुविधा सुलझती नज़र नहीं आ रही है।
- एक वयोवृद्ध ठाकरे समर्थक, शिव सेना नेता ने कटाक्ष किया, "सरकार तो बनती नहीं बी.एम.सी. का चुनाव जीतेंगे।"

# डब्ल्यु.एच.ओ. ने "मंकीपॉक्स" को "ग्लोबल एमरजैंसी" सही आंका

## हालांकि "मंकीपॉक्स" नयी बीमारी नहीं है, पहला मरीज 1970 में मिला था, परन्तु वर्तमान में इसका प्रकोप पचहत्तर देशों में दिख रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। जिस दिन डब्ल्यु.एच.ओ. ने मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया, उसके सिर्फ एक दिन बाद, यानी रविवार को ही दिल्ली में इसका पहला केस सामने आ गया। इस महीने के शुरु में, केरल में इसका पहला केस मिलने के बाद, कुल मिलाकर यह देश का चौथा केस है।

जहाँ कोविड-19 महामारी अभी तक चक्कर लगा रही है, वहीं मंकीपॉक्स वायरस के कारण लोगों में चिन्ता एवं अस्तव्यस्तता पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है।

सर्वप्रथम तो, मौजूदा मान्यता के विपरीत, मुख्य बात तो यह है कि मंकीपॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। मनुष्य में मंकीपॉक्स का पहला केस 1970 में रिकॉर्ड किया गया था। मंकीपॉक्स एक ऐसा वायरस है, जो बंदरों तथा रोडैन्ट्स (चूहा गिलहरी आदि जानवरों) द्वारा फैल सकता है। तथापि, जैसा कि इस वायरस का नाम दर्शाता है, उसके विपरीत, मंकीपॉक्स अधिकांशतः मनुष्यों के बीच के अन्तरंग सम्पर्कों के जरिये फैलता है। हालांकि, इसकी तुलना यदि चेचक (स्मॉलपॉक्स) से की जाये, तो मंकीपॉक्स को उसी के समान किन्तु उसकी अपेक्षा मन्द लक्षणों वाला रोग माना जा सकता है, लेकिन यह एक संक्रामक रोग है।

जब मंकीपॉक्स की जानकारी सबसे पहले सामने आई थी, उस समय से पूरी दुनिया में, कई सालों में गिनती के कुछ केस ही सामने आये थे। तथापि, इस साल, मई 2022 से इस रोग के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। डब्ल्यु.एच.ओ. के अनुसार, इस साल मई से लेकर अब तक इसके 16000 केस आ चुके हैं। इस समय, इसके अधिकांश केस यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में ही मिले हैं।

एन.डी.टी.वी. के एक अपडेट के अनुसार, कोविड-19 तथा अन्य बहुत सी संक्रमित होने वाली बीमारियों से अलग हटकर मंकीपॉक्स हवा से फैलने वाला वायरस नहीं है तथा आमतौर पर मन्द तथा यदा-कदा ही प्राणघातक सिद्ध होने वाला वायरस है। लेकिन, यह संक्रामक जरुर है तथा इससे पैदा होने वाले लक्षण एक-दो सप्ताह तक बने रह सकते हैं।

वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यु.एच.ओ.) ने कई अन्य कारणों से इसे एक वैश्विक आपदा घोषित किया है। एक तो यह कि, पूरी दुनिया के करीब 75 देशों में मंकीपॉक्स के केसों में वृद्धि दर्ज की गई है। अफ्रीका में इससे अब तक 4 जनों की मौत होने की खबर है।

मंकीपॉक्स के बेहद संक्रामक होने के अलावा, इसकी पुष्टि के लिए टैस्ट करना भी कठिन हैं। भारत में पिछले दो माह में मंकीपॉक्स के चार केस दर्ज किए गए हैं। तथापि, इसकी मैडिकल जांच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- महामारी घोषित होने का एक और बड़ा कारण है कि, यह बीमारी बहुत संक्रमित है। बहुत जल्दी व आसानी से जनता में फैल जाती है।
- महामारी घोषित करने का दूसरा बड़ा कारण है, इस बीमारी के बारे में भ्रांति, गलतफहमियां और चिंता भी अनावश्यक रूप से बहुत जल्दी फैली हैं। एमरजैंसी की स्थिति घोषित होने से यह आशा की जाती है कि, जनता को सही जानकारी मिलेगी और इलाज भी तेजी से फैलेगा तथा जनता बचाव के सही रास्ते पर चलेगी।

# महिला सांसद से बेअदबी!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। संसद के प्रवेश द्वार, संख्या दो पर अपनी पार्टी के तीन अन्य सांसदों के साथ बैठी तमिलनाडू की कांग्रेस सांसद ज्योतिमणी सेन्नीमलाई (47) के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथापाई की गई और इस मारपीट में उनकी सलवार घुटनों के पास से फट गई। सेन्नीमलाई को इससे पूर्व पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "देखिए एक महिला सांसद के साथ कैसा बर्ताव किया गया है। हम दूसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा सरकार की ऐसी चालबाजियों से हम नहीं डरेंगे। "प्रवेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस सांसद ज्योतिमणी सेन्नीमलाई ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि, निलंबन के बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ हाथापाई की और उनकी सलवार घुटनों के पास से फट गई।

# 'सरकार ने "मनी लॉण्डरिंग एक्ट" को हथियार बना लिया है'

## गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि, जब नैशनल हैरल्ड प्रकरण में सारे कागजात ई.डी. के पास हैं तो सोनिया जी को बुलाने व पूछताछ की क्या जरूरत है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। आज, जब सोनिया गांधी तीसरी बार एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) के समक्ष उपस्थित हुईं, तो कांग्रेस ने कहा कि देश में "ई.डी. आतंक" छाया हुआ है क्योंकि सरकार ने प्रिवैंशन ऑफ मनी-लॉन्डरिंग एक्ट को "हथियार" बना लिया है।

सूत्रों ने कहा कि, अब तक हुई दो बार की उपस्थितियों के दौरान, 75-वर्षीय सोनिया गांधी से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है जिसमें उन्होंने 65-70 प्रश्नों का सामना किया। आज उनसे 3 घंटे से अधिक समय तक की गई पूछताछ के दौरान, एजेंसी ने उनसे 30-40 प्रश्न और पूछे। सूत्रों ने आगे कहा कि, आगे और पूछताछ के लिये अभी तक उन्हें कोई नया सम्मन नहीं दिया गया है।

इससे पहले, यहाँ ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर एक संयुक्त प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके साथ जी-23 ग्रुप के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद तथा आनन्द शर्मा भी मौजूद थे, ने कहा, "देश में ई.डी. आतंक छाया हुआ है। सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, जैसा कि हमने अभी-अभी महाराष्ट्र में देखा था।"

आनन्द शर्मा ने कहा, "पी.एम.एल.ए. को हथियार का रूप दे दिया गया है, जबकि लोकतंत्र में हथियार केवल सेना के पास रहते हैं तथा समाज कानून के शासन द्वारा संचालित हुआ करता है।" संसद के दोनों सदनों से कई सांसदों के निलम्बन के मुद्दे को उठाते हुये, गहलोत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जैसा कि मालूम पड़ा, ई.डी. ने तीसरे दिन सोनिया गांधी से तीस-चालीस सवाल पूछे। पहले व दूसरे दिन लगभग 65-70, सवाल पहले ही पूछे जा चुके हैं।
- गुलाम नबी का कहना था, अब केवल "टैक्निकल" सवाल ही बचे हैं पूछने के लिये।
- आनंद शर्मा ने कहा, प्रजातंत्र में हथियार तो केवल सेना के पास होते हैं, समाज तो कानून कायदों से चलता है, पर मोदी सरकार ने तो ई.डी. का "वैपनाइज़ेशन" कर दिया है, (हथियार बना दिया है) तथा देश में भी ई.डी. का आतंक फैला रखा है।

# बार में बीफ भी बेचा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। यह बात केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए और परेशानी का सबब बन गई है कि, गोवा के आसनगांव स्थित उनकी पुत्री के सिली सोल्स कैफ़े एण्ड बार में गाय के मांस के व्यंजन परोसे जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सार्वजनिक, इस कैफ़े के मैन्यु कार्ड में गाय की जीभ और सुअर के व्यंजनों का बढ़चढ़कर उल्लेख किया गया है।

पिछले सप्ताह जब एक आर.टी.आई. में इस कैफ़े को अवैध रुप से दिए गए लायसैंस के बारे में जानकारी चाही गई थी, तब यह विवाद उठा था और मंत्री ने बार संचालन में अपनी पुत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्मृति ईरानी की बेटी के "सिलि सोल्स कैफे एण्ड बार" का मीनू सोशल मीडिया पर खूब ट्रैण्ड कर रहा है।

# सरकार का दावा है राजस्थान में सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा व जांच उपलब्ध है

## पर, जांच की सुविधा का क्या मतलब, जबकि प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे ऊपर आंके जाने वाले सरकारी मैडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कोई भी अस्पताल एन.ए.बी.एच. द्वारा प्रमाणित नहीं है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 27 जुलाई। प्रदेश में एक भी सरकारी मैडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल नैशनल एक्रडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एण्ड हैल्थकेयर प्रोवाइडर्स" (एन.ए.बी.एच.) द्वारा प्रमाणित नहीं है।

जैसा कि विदित है, एन.ए.बी.एच., केन्द्र सरकार के "क्वालिटी काउन्सिल" के अंतर्गत गठित एक "बोर्ड" है, जो सरकार तथा प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारता है, निगाह रखता है तथा अस्पतालों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक तय करता है। एन.ए.बी.एच. अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुसरण करता है। यह "बोर्ड" अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा तथा मरीजों को दी जा रही सुविधा की गुणवत्ता को परखता है और फिर अस्पताल का अधिस्वीकरण करता है।

परन्तु उल्लेखनीय है कि, राजस्थान में कोई सरकारी मैडिकल कॉलेज और उससे सम्बद्ध अस्पताल एन.ए.बी.एच. द्वारा प्रमाणित नहीं है, यहां तक कि, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और मैडिकल कॉलेज एस. एम.एस. अस्पताल भी एन.ए.बी.एच. द्वारा प्रमाणित नहीं है, और इस अस्पताल की मैडिकल लैब भी "नैशनल एक्रडिशन बोर्ड फॉर टैस्टिंग लैब्स" (एन.ए.बी.एल.) द्वारा प्रमाणित नहीं है। जैसा कि विदित है कि, एन.ए.बी.एल. किसी भी मैडिकल लैब की गुणवत्ता और "मैडिकल टैस्ट" करने की प्रक्रिया के मापदंड तय करता है, आंकता है और लैब का अधिस्वीकरण करता है।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच की सुविधा है पर हैरानी की बात है कि इनमें कोई भी अस्पताल और उसकी लैब एन.ए.बी.एच. और ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित नहीं है जिससे ना केवल भ्रष्टाचार हो सकता है बल्कि टैस्टिंग प्रक्रिया गलत होने से मरीज की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

गौरफरमाने योग्य है कि, प्रदेश में 39 मैडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पताल एन.ए.बी.एच. द्वारा प्रमाणित होने का दावा करते हैं। यह सभी मैडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल प्राइवेट संस्थाओं या पार्टियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन 39 अस्पतालों में से 28 जयपुर में हैं। तीन उदयपुर में, दो जोधपुर और अलवर, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर और कोटा में एक-एक ऐसे अस्पताल हैं, जो एन.ए.बी.एच. द्वारा प्रमाणित हैं।

जैसा कि विदित है, स्वास्थ्य, राज्य और केन्द्र, दोनों की सूची का विषय है। गत महीने "आर्काइव्ज ऑफ पैथॉलजी एण्ड लैबोरेटरी मैडिसन" जर्नल में छपी एक रिसर्च में सामने आया कि, देश भर में 555 सरकारी मैडिकल कॉलेजों में से केवल 198 की मैडिकल लैब एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित हैं।

यह रिसर्च, पी.जी.आई.एम.ई.आर. चंडीगढ़, गवरमैंट मैडिकल कॉलेज बारामती और मनिपाल अस्पताल बैंगलौर के शोधकर्ताओं ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्र सरकार ने "क्वालिटी काउन्सिल" के अंतर्गत एक बोर्ड गठित किया है, एन.ए.बी.एच. के नाम से। राजस्थान का कोई भी अस्पताल, यहां तक कि सवाई मानसिंह अस्पताल भी इस बोर्ड से अधिस्वीकृत नहीं है।
- ऐसा न होने से, न केवल भ्रष्टाचार पनपता है, बल्कि टैस्टिंग प्रक्रिया गलत होने से मरीज का इलाज भी गलत हो सकता है तथा उसका स्वास्थ्य बेवजह खतरे में पड़ सकता है।

# राहुल गांधी के 10 सवाल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को "राजा" के लिए 10 प्रश्न दागे। ज्ञातव्य है कि आजकल राहुल प्रधानमंत्री को राजा कहकर संबोधित करते हैं। उनका कहना था कि ये जनता से संबंधित वो प्रश्न हैं जिन्हें संसद के मानसून सत्र में उठाया जाना था।

उन्होंने कहा "उनकी तानाशाही देखिए कि, संसद में जो प्रश्न पूछे जाने थे उनको लेकर प्रधानमंत्री इतने खीज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राहुल गांधी ने कहा कि, इन सवालों को पूछने की कोशिश करने वालों से प्र.मंत्री इतने नाराज हो गये कि, 57 सांसदों को गिरफ्तार कर 23 को निलंबित करवा दिया।